Supplementary Demands for Grants ? First batch for 2023-2024 and Demands for Excess Grants, 2020-2021 (continued)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 18 और 19.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील जी।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील **(**औरंगाबाद**) :** सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया।

मैं महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा इलाके से आता हूं, जिसे हम सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप सरकार में आए थे, तो आपने ये दावा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी होने के बजाय, उनकी आत्महत्या दोगुनी, तिगुनी और चौगनी हो गई है, मैं यह आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं।

महोदय, मैं हिंदुस्तान के एक बहुत छोटे क्षेत्र सिर्फ मराठवाड़ा के आंकड़े बताना चाहता हूं। इस मराठवाड़ा के क्षेत्र में जनवरी से लेकर नवंबर तक 1000 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसके अंदर औरंगाबाद, जो मेरा चुनावी क्षेत्र है, वहां 160 किसानों ने आत्महत्या की, नांदेड़ में 163 किसानों ने, बीड में 253 किसानों ने, उस्मानाबाद में 161 किसानों ने और कुल मिलाकर एक छोटे से क्षेत्र की बात करें तो 1000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम किसानों के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो आखिर ये किसान इतनी आत्महत्या कैसे कर रहे हैं? मैं यह सिर्फ छोटे से क्षेत्र की बात कर रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, आप यह नारा लगाते हैं कि - ?सबका साथ, सबका विकास?, लेकिन आप मेरा विकास कैसे कर रहे हैं, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। इस फाइनेंशियल ईयर में बजटरी एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनोरिटी अफेयर्स को कितने परसेंट घटाया है? आपने यह बजट 38.3 परसेंट घटाया है। वर्ष 2023-24 का बजट ऐस्टीमेट 5,020 करोड रुपये था, लेकिन आपने उसको कम करके 3,097 करोड़ रुपये कर दिया है। मुझे मालूम है कि आप हमें थोड़े-थोड़े दिनों के बाद खुश करने के लिए नई-नई स्कीम्स लेकर आते हैं। आप कह रहे हैं कि दस स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए चलाते हैं, लेकिन उनके लिए फंडिंग और बजट एलोकेशन कैसे घटाया जा रहा है, आप यह देखिए। वर्ष 2023-24 में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट पिछले साल 1,425 करोड रुपये था, अब उसको घटाकर महज 433 करोड रुपये कर दिया गया है। आप जानते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हमारे बच्चों का है, उस स्कॉलरशिप का अमाउंट आपने इस हद तक कम कर दिया है। महोदय, मेरिट-कम-मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप में पिछले साल आपका बजट एलोकेशन 365 करोड रुपए था, आपने उस 365 करोड रुपये बजट को घटाकर 44 करोड रुपये कर दिया है। दूसरी कई स्कीम्स हैं, जिनको बहुत खूबसूरत नाम दिए गए हैं, जैसे नई उड़ान, नया

सवेरा, लेकिन बजट आप हर समय कम करते जा रहे हैं और आप ?सबका साथ, सबका विकास? का नारा लगाने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पंत प्रधान जी से आपके जरिए महंगाई को लेकर एक सवाल करना चाहता हूं। मैं जयपुर गया था। वहां पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे, जिनके ऊपर आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर थी। उसके बगल में गैस सिलेंडर था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि - मोदी की गारंटी 450 रुपये। सरकार में आ गए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर 450 रुपये का गैस सिलेंडर बेचेंगे। मैं आपके जरिए आदरणीय मंत्री कराड साहब से पूछना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमें न दीजिए, आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर दे दीजिए। आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप हर चीज को चुनाव के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे फायदा मिल सकता है। अगर आज महंगाई और बेरोजगारी के बारे में हम बात करें तो आपने हर जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर दिया है। इसका फायदा सिर्फ ठेकेदारों को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। ईपीएस-95 के जो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने 20 से 30 साल काम किया है, आपने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है, कल से वे जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप सुनिए, उन्हें 800 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये पेंशन हर महीने दी जा रही है। उसके जरिए उनको कहा जा रहा है कि इतने पैसों के अंतर्गत जी सको तो जीयो, नहीं तो मर जाओ, शोर क्यों मचाते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़ों के साथ गवर्नमेंट रिसीट्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर पिछले साल की तुलना करें तो अप्रैल-अक्टूबर 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना इस साल 7 परसेंट जीएसटी ड्रॉप हुआ है, इनकम टैक्स का ड्रॉप 2 परसेंट हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स का ड्रॉप 5 परसेंट हुआ है। अगर एवरेज निकालें तो टोटल 5 परसेंट ड्रॉप गवर्नमेंट रिसीट्स का हुआ है। अगर हम उसकी तुलना में सेम पीरियड में देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक परसेंट कम हो गया है और कैपिटल आउटले चार परसेंट कम हो गया है। हमारा आपसे यह कहना है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के जरिए आज डिफेंस के लिए 11,827 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री डिमांड रखी गई है।

हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी चीन के बारे में क्या पॉलिसी है? 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम खो चुके हैं। डेमचोक-देपसांग क्या हमारे हाथ में है? इसका जवाब आप दीजिएगा। इस पर खामोश क्यों हैं? चीन पॉलिसी के बारे में हमारा क्या रुख है, यह आप बता दीजिएगा। अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर हम सियाचिन को भी खो डालेंगे। आखिरी पॉइंट एक्सटर्नल अफेयर्स का बताना चाहता हूं। आपने सप्लिमेंटरी डिमांड्स में 11072 करोड़ रुपये इसके लिए रखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश की वैस्ट एशिया पॉलिसी क्या है? यह देश को बताइए। आज हम हिन्दुस्तान की सरकार से अपील करते हैं कि हम इस्राइल की कड़ी निंदा करते हैं। आज फिलिस्तीन में 20,000 बच्चों और महिलाओं को मारा गया है। 12 लाख लोग बेघर हो गए हैं। वहां जेनोसाइड हो रहा है और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनकर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि फौरन इसको कंडेम करे और इस्राइल गवर्नमेंट को कहे कि फौरन सीज़फायर लाया जाए। वित्त राज्य मंत्री भी औरंगाबाद से आते हैं। मैं कराड़ साहब से यह अनुरोध करूंगा कि औरंगाबाद से महज़ 30 किलोमीटर की दूरी पर नारायणपुर एक गांव है, वहां 3335 मेरे कांस्टीटुएंसी में ऐसे स्कूल्स हैं, जहां पक्की छत नहीं है, टिन के शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप यह दावा कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन इस बार किया गया है। यह पैसा जा कहां रहा है, हम आपसे यह सवाल करना चाहते हैं।

HON. CHAIRPERSON: It is already decided that the hon. Finance Minister will give her reply at sharp 3 o?clock. So, all the hon. Members are requested to conclude their speeches in five minutes.

Shri P. Ravindhranath.

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Sir, let me first of all take the opportunity to thank our hon. Prime Minister, Shri. Narendra Modi ji, and our hon. Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman ji, for sanctioning an advance release of Rs. 450 crore from the Central share of the State Disaster Relief Fund for managing the relief activities in the aftermath of Cyclone Michaung, and for approving Rs. 561 crore for the Urban Flood Mitigation Project of Chennai basin. Let me also thank our hon. Home Minister, Shri Amit Shah; hon. Defence Minister, Shri Rajnath Singh; defence forces, and NDRF for continuously rendering humanitarian aid and rescue assistance to the affected people.

Sir, the major flood in Chennai due to the rainfall triggered by Cyclone Michaung from December 2nd is the third such occurring in the last eight years. The project funded through the assistance from the National Disaster Mitigation Fund will establish a climate-resilient urban flood protection infrastructure in Chennai. I wish to request the hon. Minister of Finance that the allocation for Chennai may be further enhanced considering the capacity, risk and exposure of Chennai city. Sir, I would like to draw attention to the serious disruptions faced by the textile industry in Tamil Nadu due to the escalation of prices of cotton and yarn. A large number of spinning, weaving and garment units face the danger of closure. I wish to request the Government to initiate the following steps to rein in the price rise. As an immediate measure, stock declaration of cotton and yarn may be made mandatory for all spinning mills so that the ginners and cotton traders can obtain actual data on cotton and yarn availability. The removal of import duty on extra-long staple cotton can ensure the availability of raw materials at affordable prices to the industry to a great extent. The cash credit limit of the spinning mills to purchase cotton may be extended up to eight months in a year instead of the current three months due to the extended availability of cotton market. Similarly, the margin money sought by banks currently at 25 per cent of the purchase value may be reduced to 10 per cent. Sir, another concern is with regard to the severe crisis faced by the garment sector in Tamil Nadu. Tiruppur, which is India's largest knitwear exporting cluster, is constituted by 95 per cent of MSMEs.

Due to the economic slowdown in the west, these units are facing huge financial crisis. Lakhs of persons including the significant share of rural women who form a major share of the work force are facing the danger of being unemployed. I wish to request the Government to announce a Special Emergency Credit Line Guarantee

Scheme for the MSME sector, especially in the garment sector, so that they survive this crisis. Sir, India has been the world's fastest growing major economy in the last two years. It is also forecast to retain the top spot in 2024 as the urbanisation and industrialisation process reaches the rapid take-off phase. Our hon. Prime Minister Shri. Narendra Modi ji has always championed the role of youth in India's development. In line with his vision, *Viksit Bharat* by 2047 initiative has been launched providing a platform for the youth of our country to contribute towards making India a developed nation by 2047, in the 100th year of its Independence. Our Government has launched various schemes and initiatives to support the youth and provide them with the necessary resources to succeed. It is now up to the youth to take advantage of these opportunities and contribute positively to the development of our nation. ? (*Interruptions*) Sir, I will finish in two minutes. On agriculture front, there is an estimated 45.8 per cent of labour from this sector in 2022-23 as per the Periodic Labour Force Survey Report, which means, going forward, non-agriculture growth will have to be high enough to absorb this labour, and our economic policies should be aligned to facilitate this absorption along with the labour-substituting impact of new technology. I wish to conclude by mentioning that focus should not only be on improving the economic indicators, but then there is the increasing challenge of pollution and climate change. Sir, the severe air pollution in Delhi and other major urban areas is going to considerably reduce the life expectancy of our citizens, which impacts the socio-economic indicators of our country in the long run. Similarly, urbanisation, industrialisation and rapidly increasing incomes, especially in the middle class, will drive an enormous increase in demand for energy services. There will be more demand for power for air-conditioning, lighting and appliances as well as more liquid fuels and/or electricity. India's urban population contributes 63 per cent to the GDP which is expected to rise to 75 per cent by 2030. I wish to request that there should be dedicated budgeting to address the vulnerability to climate change impacts, such as extreme weather events, rising sea levels, and changing rainfall patterns. Recent floods in Chennai is an example, and there should be much higher spending on preventing such climate impacts in comparison to managing a disaster after the impacts.

With these words, I conclude my speech.

*m03 **SHRI SUSHIL KUMAR RINKU (JALANDHAR):** I am thankful, Hon. Chairman, Sir, that you have given me the opportunity to speak on Demands for Excess Grants. I am not asking for granting excessive money to my State. I will only ask for what is rightful and due to the state. The Central government has to provide this money to Punjab. The Rural Development Fund of Punjab has not been granted by the Central government ever since the AAP came into power in Punjab. Sir, the development work of rural roads of Punjab including Jalandhar, Adampur etc. could not be taken up due to lack of funds. Rs. 5637 crore of Rural Development Fund should be given to Punjab by the Central government. Rs. 621 crore of National Health Mission fund has also not been given to Punjab by the Central government.

The HRD minister had objected and said that Punjab government is misusing central government funds on ?Mohalla Clinic? scheme. Sir, in Punjab, 660 ?Mohalla Clinics? have been started by AAP. Lakhs of people have benefitted from this scheme. Punjab government has clarified that not a single rupee of National Health Mission will be spent on Mohalla Clinics. Punjab government will utilise its own funds for this purpose.

Sir, Rs. 850 crore of NDF is due to Punjab and the Central government is yet to give this amount. About Rs. 1800 crore of Special Assistance Fund is also to be given to Punjab by the Central government. A total of Rs. 10,000 crore is yet to be given to Punjab by the Central government. This fund should be released to Punjab Government at the earliest. Punjab government had to knock at the doors of Supreme Court to get these funds released. Punjab government did not want to do this.

So, I urge upon the Central government to release these funds to Punjab so that we can undertake stopped development works in the State.

Thank You.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you very much Chairperson, Sir. I strongly oppose the Supplementary Demands for Grant. Political philosopher Niccolo Machiavelli warned that a prince who is without any wisdom himself cannot be well advised. Our Prime Minister is an unwise prince who can never be well advised. One of the major functions of Parliament is to advise the Executive branch. But as the prince is unwise, the advice goes fruitless.

We have heard, ?*Achhe Din Aane Wale Hai*?. Since the 2014 Election season and with the hike in railway fare, freight rate, petrol and diesel prices, sugar and LPG prices,

is the Government doing what it had promised? Interestingly, the All-India Anti-Corruption and Citizens Welfare Core Committee had filed a PIL in the Bombay High Court alleging a criminal breach of trust by the Modi Government over the increase in railway ticket fare and prices of commodities. Although the plea was rejected by the court, the Modi Government is being blamed for not fulfilling its promise and breaking people?s trust.

The dream of the third largest economy in the world with five-trillion dollar GDP by 2030 is a great one. But, let us examine and compare India?s GDP with the GDPs of the countries having the first and second largest GDPs. USA holds the first largest GDP of 25 trillion US dollars now. The US population is only 34 crores. See how big is the *per capita* income and hence the standard of living in the US. The second highest GDP is that of China with 18 trillion US dollars. Of course, the second largest population in the world of 142.57 crores, makes India?s *per capita* income and standard of living very low as compared to the US. What is the present level of GDP of India? It is only 3.7 trillion dollars whereas India holds the largest population in the world, that is 142.86 crore. What would be the *per capita* income compared to the US and China? Foreign Direct Investment in retail trade has almost spoiled the micro, small & medium enterprises. If five trillion-dollar GDP is shared among the corporates, what is the inclusive growth strategy? The National Health Policy 2017 mandates that the health expenditure should be raised to eight per cent of the GSDP of the States by 2022 and 2.5 per cent of the GDP by the Centre by 2022. But in the 2023-24 Budget, the Centre has allocated only 1.97 per cent of the total expenditure which is less than one per cent of the GDP. Remember the floating of dead bodies on the river during COVID-19. So, I would request the Government to release more funds as supplementary grants. When countries like China spend five per cent to six per cent of GDP on education, India allocates just 2.5 per cent of the total expenditure on education, not of GDP. The dropout rate is on the increase which is alarmingly high among the SC and ST students. It should be remembered that the educated and skilled youth are the dividend of the country, not the unemployed illiterates. India continues to grapple with persistent unemployment concerns, marked by fluctuations evident across various regions and sectors.

According to the recent Bloomberg Report citing data from the Centre for Monitoring Indian Economy for July, the national unemployment rate stands at 7.95 per cent as of July, 2023. Agriculture, which is India?s largest private sector, is burdened with an archaic business model suffering from Government?s controls.

The farmer must be able to leverage land, labour, and capital like any other entrepreneur to be viable but lacks access to affordable credit, a reliable supply chain of inputs, and access to markets. In 2020, over 10,677 farmers, that is, 29 in a day or over one every hour, committed suicide, and estimates place the cumulative figure for two decades at over four lakhs. Agricultural input prices have to be raised to the maximum. Now, farmers are given freebies of Rs. 6000 which they will utilise not on agriculture but on other essentials. About 10 crore poor families are given cooking gas connections with cylinders. But a cylinder at the rate of Rs. 912 cannot be afforded by them. Due to the changes in the norms by the 15th Finance Commission, Kerala?s share from the divisible pool declined from 2.5 per cent in the 14th Finance Commission to 1.93 per cent in the 15th Finance Commission. Hence, the State is under severe fiscal stress. The population of those above 60 years is comparatively high in Kerala. A minimum grant of Rs. 10,000 crore is necessary to address the geriatric care.

I am now concluding only with one line. Politics without principle is one of the seven deadly sins according to Mahatma Gandhi.

Hon. Chairperson, Sir, I am sorry to say that Modi Sarkar is the epitome of politics without principle.

Thank you very much.

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सर, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। हम इसके सपोर्ट में हैं। चूंकि यह इलैक्शन बजट है और हमें भी इलैक्शन में जाना है, इसलिए सब को अपने-अपने हिसाब से बोलना ही पड़ेगा। Sir, my first demand is the allocation of fund to control flood and erosion in Assam especially in Fakirganj, South Salmara, Mankachar, Jaleswar, Goalpara, Dhubri, Bilasipara, etc. My second demand is the allocation of fund for construction of four-lane National Highway in Barpeta starting from Amingaon, Guwahati to North Salmara via Jania, Barpeta in the State of Assam. The third demand is the allocation of fund for the establishment of Central Universities and Medical Colleges in Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipara, Goalpara, Barpeta, Nagaon, Karimganj, and Hojai. The fourth demand is the allocation of fund for setting up hospitals in Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipara, Goalpara, Barpeta, Nagaon, Hojai and Karimganj. The fifth demand is the allocation of fund for the construction of new railway line from Bongaigaon, Abhayapuri to Amingaon, Guwahati via Jania and Barpeta town. My sixth demand is the allocation of fund for construction of RCC bridge over Brahmaputra River at Barpeta district either Bamun Dongra to Kholabandha or Bahari to Kasumara in Barpeta. My

seventh demand is the allocation of fund for construction of RCC bridge over Beki River at Majid Bhita or Chikni. सर, यह लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और इसको जरूर हो जाना चाहिए। My eighth demand is the construction of RCC bridge over Jaljali river at Bagmara to Simlitola, Alopoti to Nagarbera and Say Shiman to Dolgoma. My ninth demand is the allocation of fund for construction of RCC bridge starting from Bhaghmara Char to Simolitala Bazar.

My tenth demand is the fund for construction of RCC Bridge starting from Chaysimana to Dolgoma. My eleventh demand is the fund for construction of RCC bridge starting from Majar Char to Nagarbera. My twelfth demand is the fund for construction of RCC bridge starting from Uzirar Char ? Mowkhowa to Dekdhowa. My thirteenth demand is construction of RCC bridge starting from north bank Habidongra to south bank Kholabhandha over river Brahmapurtra. My fourteenth demand is relating to fund for setting up jute industry in Dhubri, Goalpara, Mankachar, South Salmara and my last demand is the fund for setting up heavy industries in Assam especially Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipara, Goalpara, Barpeta, Nagaon, Hojai, Karimganj etc. Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this issue. We are in support of this Supplementary Demands for Grants.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to oppose the way the Supplementary Demands for Grants have been laid on the Table. It is the reflection of the lack of Government?s vision.

Sir, the Supplementary Demands for Grants contains 79 Demands and four appropriations. Gross additional expenditure is Rs. 129348.85 crore, net cash outgo is Rs. 58378.21 crore, and saving recovery is Rs. 70968 crore.

सुबह से शाम तक सदन में हम लोग सुनते आ रहे हैं ?मोदी की गारंटी।? अब यह नया नारा शुरू हो गया है। पहले नारा था- ?मोदी है तो मुमकिन है।? अब नारा बदल गया है और ?मोदी की गारंटी? आ गया है। यह है नारों की सरकार, इसलिए इन लोगों के लिए चिन्ता नहीं करने की है दरकार।

बात यह है कि यह गारंटी किस पर है। जब गारंटी दी जाती है, तो उसकी एक वारंटी पीरियड भी होती है। क्या गारंटी के साथ वारंटी पीरियड है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कहा गया था कि दो करोड़ सालाना नौकरियाँ मिलेंगी, वह गारंटी खो गई। कभी कहा गया था कि बाहर से कालाधन लाकर हरेक लोगों की जेब में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, वह गारंटी भी चली गई। यह भी कहा गया था कि नोटबंदी के कारण सारा ब्लैकमनी बैंक्स में वापस आ जाएगा, 99.68 परसेंट सफेद मनी आ गया। इस तरह से, केवल गारंटी ही गारंटी है, लेकिन इस गारंटी के साथ कोई वारंटी नहीं है। सरकार कहती है कि हम इस जमाने में थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेंगे और

वर्ष 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। इसे महान कंट्री बनाने में एक हजार साल लगेंगे। क्या गारंटी के लिए हम लोग एक हजार साल इंतजार करें? अभी हमारे साथ में कुछ लोग आए, इसलिए मैंने आप लोगों के बारे में कुछ कहा।

सर, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जयंत सिन्हा जी कह रहे थे कि मार्केट की कैपिट्लाइजेशन 4-5 ट्रिलियन हो गई है। _

-

14.32 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

I would like to quote Raghuram Rajan ji. The euphoria on Dalal Street about India joining the elite group of countries with four trillion market capitalization and sensex hitting all-time record high level is not a good indicator of broader economic success, argues former RBI Governor.

In the just released book ?Breaking the Mould?, Rajan and economist Rohit Lamba say that the stock market offers a misleading picture of the broader economy as the big are getting bigger and small ones are getting smaller. For a variety of reasons, including demonetization, the pandemic and the implementation of GST, we have seen an increase in the profitability of large funds in the country. While small and informal funds are doing relatively poor but only the formal sector is quoted on the stock markets which offers a misleading picture of the broader economy.

रघुराम राजन क्या कहते हैं, आप तो उसे नहीं मानेंगे। सुबह से शाम तक सारे सदन में केवल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी का स्वर गूंजता है। मोदी जी के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है, मोदी जी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनमें से कोई गीता का पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है और कोई कुरान का पाठ करता है।

सदन में आने से पहले आप मोदी स्तुति, मोदी पाठ करने के बाद सदन में आया कीजिए। हर व्यक्ति, जो चर्चा में शामिल होता है, कम से कम दस प्रतिशत समय मोदी जी का गुणगान करने के लिए ये अपनी तरफ से ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपको क्या परेशानी है?

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** सर, मैं सलाह दे रहा हूं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप सलाह मत दीजिए। आप सदन के नेता हैं।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** मैडम निर्मला सीतारमण जी यहां हैं। Madam, I would like to draw your attention to a very pertinent issue. One of the main aims of awarding contracts to the MSME sector through the MSME portal is to promote ostensibly the small enterprises for bringing about transparency in tendering process and to meet the ends of Atmanirbhar Bharat.

As per the system currently being followed, small enterprises which bid for and secure contracts through the GeM portal have to pay a fee of 0.5 per cent of the contracted amount. Thus, a person or an enterprise who secures a contract of, say, Rs.10 crore, will have to immediately pay a fee of Rs.10 lakhs. This amount of fee, you must appreciate, is substantial for a small enterprise and would only eat up the capital of the small entrepreneurs or firms. The simple point that is being made here is that the fee of taking up the contracted item of works through the GeM portal should not be such that it would be a burden for the small enterprises. It ends up eating into the likely profit margin and does not contribute to making the country Atmanirbhar. For achieving the goal of promoting small enterprises, I would suggest that the Government should do away with the current system of upfront payment of 0.5 per cent of the contracted amount immediately by the enterprise concerned.

Instead, a more viable and objective method of charging fees for the contracted amount on the portal could be introduced by way of having a graded or slab-wise system of fees, prescribed starting from a contract amount of Rs.50 crore. A slab-wise system of the fee prescribed for contracted amount of Rs.50 crore and above will go a long way in helping the small enterprises and entrepreneurs by saving their capital and improving their profit margin.

मैडम, मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर कोई इंटरप्रेन्योर होता है, तो उसको GEM पोर्टल में शामिल होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा असर एमएसएमई सेक्टर में होता है। आप एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की बजाए व्हीलचेयर में बैठा देते हैं। इसलिए, मैं आपके संज्ञान में यह मुद्दा रख रहा हूं।

मैडम, यह कहा जाता है कि हमारा देश रोजाना तरक्की कर रहा है। हमें रोजाना बिलियन-ट्रिलियन की बातें सुनते-सुनते ?मुंगेरीलाल के सुनहरे सपने? याद आते हैं। इसलिए**,** मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं to better understand the extent of food inflation. Rating agency CRISIL releases a monthly Roti Rice Rate which tracks price changes of the various commodities used to prepare a vegetarian and a non-vegetarian thali.

Madam, the cost of a vegetarian thali rose by 24 per cent to Rs.33.8 and that of a non-vegetarian thali by 13 per cent to Rs.67.3 in August, as compared to the same period last year. The inflationary pressure due to rising food prices and fuel and a depreciative rupee have resulted in the people relying on their savings to meet their consumption needs. The net household savings of Indians dropped to a five-decade low.

मैडम, मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे देश में आम लोगों का खर्चा करने का क्या पैरामीटर है? उनकी आज की ताजा हालत क्या है? There is a survey which would enable us to adequately gauge as to how much money people spend on their consumption needs. The Consumer Expenditure Survey has been carried out by your Government. But its findings have been withheld. The results for 2022-23 and 2023-24 of CES are likely to come only after the 2024 elections.

The findings of a similar exercise done by the Government in 2017 and in 2018 were also withheld but the leaked data had shown a rise in poverty levels and a 45-year high unemployment. I do not know, Madam, whether you will be subscribing to my views or not but the issue is, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता है, मोदी की विकसित गाड़ी चलती है और काफी रफ्तार से चलती है, आप लोगों के कहने के मुताबिक, तो आपको 5 साल के लिए मुफ्त राशन की गारंटी देने की क्या जरूरत होती है? आप बताइए। आपको क्या जरूरत होती है? अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता है, तो ये इतने सारे रेवड़ी की बात जो कह रहे थे, उस रेवड़ी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों बैचेन रहते हैं, क्योंकि वे खुद रेवड़ी देने में आज काफी अग्रसर हो चुके हैं।

मैडम, मैं ये दो-चार बातें आपसे कहना चाहता हूँ। आप देखिए कि आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 125 देशों में 111 वीं है। What does it indicate? As far as the per capita income vis-à-vis GDP is concerned, we are now at 138th position in the world. In 2023, the trade deficit hit a record high of USD 31.46 billion, that means, our economy was beleaguered by high inflation, unstable rupee, and current account deficit. नार्मल जीडीपी हमारा फिफ्थ, पीपीपी में थर्ड है। मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे देश की पर-कैपिटा इन्कम आप देखिए। यह नॉमिनल में 2,612 डॉलर है और पीपीपी में 9,183 डॉलर है। मैं कहना चाहता हूँ कि आम लोगों को गुमराह करना सरकार का काम नहीं हो सकता है और इसलिए सरकार इससे बाज आए। रोजाना लोगों को जीडीपी की कहानी सुनायी जाती है, लेकिन लोगों की जेब की हालत क्या है, लोगों के घर की हालत क्या है, लोगों को पेट पालने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, इसके लिए कोई सही दिशा दिखाने में आप विफल रही हैं। आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी फिफ्थ लारजेस्ट इन दी वर्ल्ड हो गई है और हम थर्ड लारजेस्ट होने जा रहे हैं। आप गौर कीजिए। India?s GDP data has huge errors. Since 2016-17, when demonetisation was announced, the unorganised sector has been on the decline but the official data does not capture it. The organised sector is taken to be a proxy of the non-agricultural unorganised sector. आपने क्या किया, आपने क्रोनी कैपिटलिज्म को मदद की और क्रोनी कैपिटलिज्म की

मदद के चलते हमारे देश से पलायन होता जा रहा है। अगर आप सही तरह से जवाब दोगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए फ्लाइट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमारे देश में शुरू हो चुकी है। The resulting damage to the business environment has led to tens of thousands of high net worth Indians leaving India since 2014, and lakhs have given up Indian citizenship recently. यह सही है या नहीं, यह आप बताइए। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है या नहीं। नीति आयोग का कहना है कि हमारे देश में मल्टिडाइमेन्शनल पावर्टी अभी 4.96 परसेंट हो गई है। The recently released Multi-dimensional Poverty Index by UNDP put the figure at 16.4 per cent. यह क्या दर्शाता है? हम जो भी बात करें, लेकिन there is another side behind all the hue and cry and behind all the high-octane propaganda by this Government.

आप ये सप्लीमेन्टरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लाई हैं, इसमें आप एग्रीकल्चर, कैमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनीज को और सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देने को कह रही हैं। आपको इतने दिन तक यह याद नहीं आया। Government?s DFG probably underestimates the actual cost of the subsidy to the exchequer.

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी और यह सरकार आर्गेनिक फर्टिलाइजर और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं। आप सालाना सब्सिडी फर्टिलाइजर में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपये की दे रहे हैं। उसमें आर्गेनिक और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर का कितना हिस्सा है? हमारी जमीन खराब होती जा रही है। हमारी जमीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए आर्गेनिक और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है। बाजार में जो आर्गेनिक और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर मिलते हैं, वे नकली होते हैं। इसकी जांच करने की लैबोरेट्री नहीं है। आप बताएं कि आपकी सब्सिडी में आर्गेनिक और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर के लिए कितना हिस्सा रखा गया है? मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कीजिए। आप ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल कीजिए। इससे फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि क्रोनी केपिटलिज्म का असर क्या होता है। Cronyism weakens economic administration and leads to the persistence of black income generation. A decline in the black economy would have led to India?s Tax-to-GDP ratio to rise. It has remained at about 16 to 17 per cent in the last 10 years. Direct tax as a per cent of GDP has hovered at about 5.5 to six per cent. If the black money had been checked, it should have conservatively risen to 12 per cent of GDP. Increased GST collections post pandemic are being shown as an example of better compliance. But this is expected due to high inflation, increase in imports, and growth of the organised sector at the expense of the unorganised sector. A large number of fake companies to claim input credit are being detected every month and official evasion is running into tens of thousands of crores.

महोदय, जो बात बाहर कही जाती है, अंदर से उस बात में काफी फर्क निकल कर आता है। मैं एक और सलाह देना चाहता हूं कि यदि आप मुफ्त में राशन देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन-सा सेंसस अपनाते हैं? आप

पुराना सेंसस वर्ष 2013 का अपनाते हैं लेकिन आज वर्ष 2023 खत्म होने जा रहा है। पिछले दस सालों से गरीब लोग मुफ्त राशन से वंचित रह गए हैं, लेकिन आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं मैडम निर्मला सीतारमण जी से दरख्वास्त करता हूं कि आप बहुत कुछ जरूर सोचती हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन आपके खिलाफ एक शिकायत भी है। आपने अपनी बेटी की शादी में हम में से किसी को न्योता नहीं दिया, एक लड्डू तक नहीं खिलाया। आप हमें एक दिन लड्डू जरूर खिलाएं। हम आपकी बेटी के लिए मंगल कामना करते हैं।

महोदय, यहां जो बात हमने उठाई है, आप उसके बारे में जरूर बताएं और सही दिशा में देश को आगे ले जाने की मैडम अपनी सोच सदन के सामने रखें। नमस्कार।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, please give me five minutes. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** बहुत लम्बी डिबेट हो गई है।

वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री **(**श्रीमती निर्मला सीतारमण**):** अध्यक्ष जी, यह इस साल का फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री है।? (व्यवधान) Sir, in this First Batch of Supplementary Demands for Grants, I want to emphasize on the fact that normally, there are three supplementaries which come. ? (*Interruptions*) लेकिन पिछले दो-तीन साल से हमारी सरकार बजट एस्टीमेट के समय से लेकर रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्टेज तक आंकड़े सही करके सदन के पटल पर रखती है, इसलिए इतनी बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आपके सामने इसे शुरुआत में ही रख रही हूं। जब सरकार अपने आंकड़े बजट के विषय में ज्यादा ध्यान देकर तैयार करती है, तो सप्लीमेंट्री में इतनी बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे पिछले दो-तीन साल के रिकार्ड में हम दो ही बार सप्लीमेंट्री बजट लाए हैं और इस बार पहली बार ला रहे हैं। मैं उम्मीद रखती हूं कि दूसरी बार आवश्यकता पड़ेगी तो आऊंगी, लेकिन तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि कितने ध्यान से बारीक विषयों के ऊपर ध्यान रखकर हम बजट तैयार करते हैं, यह बात मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं।? (व्यवधान)

Sir, in this first batch of Supplementary Demands for Grants, we are placing 79 demands और इसमें चार एप्रोप्रिएशन के विषय हैं। The Supreme Court of India, Central Vigilance Commission?s staff, household and allowances of the Rashtrapati ji and also the Union Public Service Commission, इन चारों विषयों को एप्रोप्रिएशन में ला रहे हैं, जो एकदम आवश्यक है। इसलिए हम इन विषयों को इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जोड़ रहे हैं। The gross additional expenditure is about 1.29 lakh crore and of this, the net cash outgo is estimated to be Rs.58,378 crore. So, from the net cash outgo, Rs.53,858 crore shall go under the revenue section and Rs.4,520 crore shall go under the capital section. यह 1.29 लाख करोड़ रुपये की जो हमारी मांग है, जिसे हम सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के फर्स्ट बैच में लाए हैं। They are going out in four different Heads. पहला, 58,378 करोड़ रुपये एडिशनल कैश आउटगो है। Rs.70,968.15 crore is technical supplementary. And, this is

matched by the surrender of savings in different sections with the demand or enhanced receipts, recoveries and so on. About Rs.2.49 crore is token supplementary to enable reappropriation of funds towards items of greater priority. इस टेक्निकल डिटेल्स को मैं हाउस के सामने रख रही हूं।

महोदय, इस मौके पर मैं श्री पिनाकी मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि सरकार की बजट प्रक्रिया के ऊपर, he had some kind words to say, particularly on the fiscal management.

महोदय, मैं सभी सांसदगण के सामने इस विषय को रखना चाहती हूं कि फिस्कल मैटर्स में, the guidance of the former Chief Minister of Gujarat or the current Prime Minister Shri Narendra Modi is based out of his experience of managing budgets in his then State, Gujarat, and now for the country. So, fiscal prudence has been kept top of the priority while at the same time not denying any welfare funds. इसलिए गरीबों की देखभाल करते हुए फिस्कल प्रूडेंस को मेन्टेन करते हुए और जहां पैसे फिजूल में खर्च होते हैं, पैसा बैठा रहता है और ग्राउण्ड में उसका खर्च नहीं होता है, इन सबको ठीक से संभालने के कारण आज हमारी इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेटल्स में सही रास्ते पर चल रही है। इसी के कारण, हम सबसे ज्यादा तेज रफ्तार में ग्रो करने वाली एकमात्र इकोनॉमी हैं। क्वार्टर-2 के 7.6 प्रतिशत की हमारी ग्रोथ दुनिया में सर्वाधिक है।

सर, हम जो पैसे ले रहे हैं, उसे किस कारण से ले रहे हैं, आपकी अनुमति से उसे क्यों ले रहे हैं और इस पैसे का किस हेड में जाना आवश्यक होगा, इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की ब्रीफ समरी में मैं यह सब कहना चाहती हूं।

सर, हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स की बात की। उसके ऊपर यह सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। इसलिए इस बजट में हम न्यूट्रिएंट-बेस्ड फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी के लिए 16,300 करोड़ रुपये ले रहे हैं।

This is being funded through cash supplementary and savings from the demand. सर, कैपिटल इन्फ्यूज़न में पिछले 4 साल से हर बजट में डिस्कशन में बीएसएनएल के ऊपर सभी माननीय सांसदों का ध्यान जाता है कि हमारे बीएसएनएल को क्या हो रहा है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के आरोप तक हैं कि बीएसएनएल को आप सेल करने के लिए इरादा रख रहे हैं। जबकि मैं हर बजट में बीएसएनएल के लिए प्रावधान करती आ रही हूँ। अभी भी 11,850 करोड़ रुपये बीएसएनएल के लिए कैपिटल इंफ्यूज़न कर रहे हैं। बीएसएनएल का ध्यान रखने वाली मोदी जी की सरकार है। पिछली सरकार को बीएसएनएल के लिए क्या नहीं करना था, और क्या नहीं किया, उसके बारे में हर बजट स्पीच में हमने ज़िक्र भी किया है कि बीएसएनएल की बुरी हालत का प्राइमरी कारण, 10 साल की यूपीए की सरकार में रहा है, जहां उसको दरकिनार कर के बीएसएनएल की प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं किया गया। मगर हम हर बजट में कुछ न कुछ देते आ रहे हैं। इस सप्लिमेंट्री डिमांड में भी 11,850 करोड़ रुपये कैपिटल इंफ्यूज़न बीएसएनएल के लिए कर रहे हैं। साथ ही, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए भी अलग से पैसा, इसमें से ही 1,434 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए 1,434 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

महोदय, जो वायदा हमने गरीब लोगों से किया था, उनमें हम ?पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना? के तहत अगले 5 सालों तक मुफ्त अनाज राशन कार्ड पर दे रहे हैं एवं इसके लिए 5,500 करोड़ रुपये इस सप्लिमेंट्री डिमांड्स के द्वारा हम दे रहे हैं। महोदय, उज्ज्वला योजना में नंबर ऑफ हाऊसहोल्ड्स बढ़ाने के लिए जो वायदा माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया, उसके लिए 8,500 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जिससे एलपीजी का कनेक्शन गरीब के घरों तक जाए और पूरा सैचुरेशन हो जाए, जिससे एक भी गरीब ऐसा नहीं छूटना चाहिए। साथ ही, जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, ऐसे आरोप नहीं होंगे। सभी लोगों को, जो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरी होने की पात्रता रखते हैं, उनके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा। सर, मनरेगो के लिए बार-बार हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम इतना पैसा मनरेगा के लिए नहीं देते हैं। अधीर जी ने भी इस बात को बार-बार उठाया है। यह स्कीम उनकी सरकार की थी और कहते हैं कि हम उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। सर, मैं उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ, मगर वे यह भूल जाते हैं कि उनकी इस स्कीम का प्राइमरी फोकस है कि यह डिमांड बेस्ड स्कीम है। जब डिमांड ऊपर उठेगी, तब उनके लिए हम पैसा देंगे। सर, हमने 60,000 करोड़ रुपये बजट एस्टिमेट के समय दिया है। अभी डिमांड आने के कारण 20,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। उसके लिए लोक सभा से अनुमति मिलती है तो इस साल दिसंबर तक तो कुल मिला कर 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान मनरेगा के लिए इस हाऊस से मिल जाएगा। सर, माननीय सांसदों को याद होगा कि कोविड के समय भी जब जरूरत पड़ी, तब हमने 1 लाख करोड़ रुपये मनरेगा के लिए बजट के द्वारा पैसा दिया है। जब माँग उठती है, तब तुरंत उसको रेस्पॉन्ड भी करते हैं। सर, जम्मू और कश्मीर से additional expenditure towards Central assistance and resource gap meet करने के लिए जेएण्डके सरकार से माँग आई है। इसीलिए उनको 3,170 करोड़ रुपये इस सप्लिमेंट्री डिमांड के द्वारा हम दे रहे हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है, जिसका नाम ?पीएम विश्वकर्मा? है।

15.00 hrs

उसमें 18 ऐसी चीजें हैं, जिनको ग्रामीण स्तर पर हाथों का उपयोग करके बनाया जाता है। जो लोग अच्छी-अच्छी चीजें बनाते हैं, चाहे लोहार हो या सोनार हो, उन सबके 18 ऐसे ट्रेड्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से 15 अगस्त, 2023 को पीएम-विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया। उसके लिए हम इस साल 989.52 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं।

सर, इसके साथ ही एक्सेस ग्रांट का भी एक बिल आपके सामने है। वर्ष 2020-21 में जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ, उसके लिए ऑडिट वगैरह होने के बाद अभी हम आपके सामने आ रहे हैं। 1,18,651 करोड़ रुपये का एक्सपेंडिचर in two grants and one appropriation, हम आपके सामने रख रहे हैं। जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है, मैं उसके विवरण में नहीं जा रही हूं, क्योंकि इसमें और टाइम लग जाएगा। मैं मेम्बर्स के प्रश्नों का जवाब देना चाहती हूं। जो पेपर मेम्बर्स के साथ शेयर हुआ है, उसमें एक्सेस एक्सपेंडिचर का विवरण है।

सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर बहुत सारे मेम्बर्स ने बात की है। उस पर बहुत वरिष्ठ सांसद प्रो. सौगत राय ने बात की, मगर अभी वह हाउस में नहीं है। इसीलिए, मैं उनके प्रश्नों का जवाब अभी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आपके पहले के ऑर्डर याद हैं। So, I am not answering his questions although he had raised a lot of questions which are only half-truths; and he does not come out with details.

मेरे सामने सांसद सुप्रिया सुले जी बैठी हैं। मैं उनके विषय को उठाना चाहती हूं। We certainly have prioritised on balancing the interests of the farmers and the interests of the consumers. Most often when we do this, we have a situation where when prices go up, you need to have supply side constraints removed, bring all the goods to the market - even if it means that you have to purchase it *ad hoc* from some large growing areas and bring it to the markets - for the consumers? sake. At this time, we are equally conscious if the price at which we procure from the farmers is adequate or meeting his requirement or not. So, it is always a question of balancing between the interests of the farmers and the interests of the consumers, but more often, inclined towards the farmers because we should not obtain or procure his goods at a rate lower than the MSP. That consideration has always been there in my mind. But for goods or farm products which do not have an MSP declared, it is constantly searching for the right fair price which is determined by the market forces rather than we as Government determining it. So, as a result, I want to say that particularly in food grain prices, you find that the inflation had come down to 4.87 per cent as of October, 2023. There has been a more than five-fold rise in the Union Agriculture Budget of Rs. 1.25 lakh crores from Rs. 21,900 crore in 2013-14.

Hon. Member also raised the issue of the uncertainties in the export and banning of exports. Sometimes you allow exports and sometimes you do not. So, as a result of this fluctuating policy, you have a situation where farmers, particularly those who are growing onions, do have an issue saying that if they are able to fetch a better price by exporting, by banning that export, we are denying them that opportunity to get a better price. I understand their concern, but if there are crop shortages and if there are difficulties of getting something as essential as onion to the market, we will have to ensure that the Indian consumers get priority and therefore, sometimes we need to come up with such measures. But I quite understand the sentiments with which Member Supriya Sule has spoken.

Sir, the increase in MSP itself helps us to address the issues or concerns of the farmers.

I want to highlight the increase in MSPs, particularly the latest increase for the Rabi marketing season of 2024-25. I will name the crops and state the MSP which existed in 2014-15. Then, I will compare that with the MSP of 2024-25, and say what is the increase. For example, I start with wheat. In 2014-15, the MSP for Rabi marketing season was Rs. 1,400 per quintal. The MSP for Rabi marketing season for

2024-25, which is the current Rabi marketing season, is Rs. 2,275 per quintal. It was Rs. 1,400 then. Now, it is Rs. 2,275. There is an increase of Rs. 875, which is a 63 per cent increase. Now, if we look at barley, it was Rs. 1,100. Now, it is Rs. 1,850, which is a 68 per cent increase. For gram, it was Rs. 3,100. Now, it is Rs. 5,440. For masoor, it was Rs. 2,950. Now, it is Rs. 6,425 per quintal, which is a 118 per cent increase. For rapeseed and mustard, it was Rs. 3,050. Now, it is Rs. 5,650 per quintal, which is an 85 per cent increase. For safflower, it was Rs. 3,000. Now, it is Rs. 5,800, which is a 93 per cent increase. The MSP itself has increased manifold between 2014 and now. So, this is taking care of the farmers. We have not just increased the MSP but we also procure from the farmers, and therefore, money goes directly into the hands of the farmers. ? (*Interruptions*)

I would like to highlight about the wheat procurement, which will be of interest for the hon. Member who is now saying something. I would like to place this number before the hon. Member who is from Punjab. Through the hon. Speaker, I would like to inform him that MSP payment for wheat during 2006-14 was Rs. 2.39 lakh crore. That is all that went to the farmers. Now, Rs. 4.52 lakh crore, two times more, is going to the farmers who are growing wheat, be they in Punjab, be they in Haryana, or be they in Madhya Pradesh.

Similarly, as regards pulses, 1.52 lakh metric tons were procured in 2014. Now, in 2023, 82.21 lakh metric tons were procured. So, there is 54 times increase in the procurement of pulses. As regards MSP for paddy, Rs. 3.09 lakh crore went directly into the accounts of the farmers during 2006-14. Now, between 2014 and 2022, if you see the difference, it is Rs. 10.06 lakh crore. So, 3.3 times more MSP goes to the paddy farmers.

Sir, I am not sure if Shri Dinesh Chandra Yadav is here. If he is not here, as per the direction given by the hon. Speaker, I would not respond to the issue. I cannot see the hon. Member. He is not here. So, I move over.

माननीय अध्यक्ष **:** वित्त मंत्री जी ने एक-एक मेंबर का सीरियस तरीके से नोट किया है और एक**-**एक मेंबर का जवाब दे रही हैं।

? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: The direction should be reviewed because whatever is stated in the House, it is the responsibility of the Government to respond whether the hon. Member is present or not.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, do I follow your old order or is there a new order? ? (*Interruptions*)

Another Member raised an issue. Again, I am not sure if I am able to spot Shri Sushil Kumar Rinku. If the Member is here, I will answer. The hon. Member is here.

Funds are not being released to Punjab, especially for rural development issues since the Government has come to power is what the allegation was. I would like to answer the hon. Member. Some scheme guidelines have been given for the schemes which go to the States, and when the compliance is not there, releases are not being made. Punjab will perhaps have to go back to check if they are following the guidelines issued for the schemes.

There are common reasons for not just Punjab, but the other States also which have a problem. The problem is that the Centrally-Sponsored Scheme funds are not released or are released with a delay by the Ministries. If there is a high bank balance, i.e. unspent balance, which remains in the account in the Single Nodal Agency of the scheme, obviously, till that is spent, the next instalment does not come. The second reason is non-submission of annual action plans by the States. Without the action plan, we are not able to see where that Central Scheme is getting executed. The third reason is the Outstanding Utilisation Certificates not coming on time. यह सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, जहाँ वर्तित है वहां भी है। आउटस्टैंडिंग यूटिलाईज़ेशन सर्टिफिकेट जब नहीं आता है तो नहीं मिलता। The fourth reason is violation of branding and naming guidelines of CSS. ज्यादातर स्टेट्स में प्रॉब्लम थी, सिस्टम को बदलने के बाद उनका पैसा उनके पास जा रहा है। The fifth reason is non-transfer of previously released Central share or State share into the SNA Account by the State Governments. The Single Nodal Agency Account was created after quite a lot of discussions with the States. जहां सेंट्रल स्कीम्स का पैसा, जहां सेंटर और स्टेट्स का शेयर है, अगर स्टेट का शेयर सिंगल नोडल एजेंसी के अकाउंट में आ जाता है तो उसी क्षण सेंटर का शेयर भी पहुंच जाता है। अगर स्टेट का पैसा उस सिंगल नोडल अकाउंट में नहीं डालते हैं तो सेंटर इंतजार करके देखता रहता है। सेंटर ने पैसा नहीं दिया, यह आरोप सही नहीं है। जिस मोमेंट में आप सिंगल नोडल अकाउंट में पैसा डालते हैं तो सेंटर का पैसा भी उसमें आ जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स को इस विषय को समझने में थोड़ी देर लगी, मगर अब ठीक चल रहा है। Another reason is non-remittance of interest accrued in SNA account. To the consolidated fund, एसएनए अकाउंट का इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर वह इंटरेस्ट ठीक से जमा नहीं होता है, उसके कारण भी डिले हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, Rs. 1,104 crore have been provided to Punjab under Rural Infra Development Fund by NABARD since Aam Admi Party came to power back in March, 2022. उदाहरण है, जहां सेंट्रल स्कीम का पैसा गया, मैं मेंबर को याद दिलाना चाहती हूं।

Shri Imtiyaz Jaleel raised some issues like SDG has some allocation for defence but what is the policy on China when we have lost twenty posts? यह उनका प्रश्न था। He also said that we should condemn Israel for violence. He said that in Narayanpur, which is close to Aurangabad, schools do not have roof. This is directly not much of an issue on the Supplementary Demands for Grants. Hence, there was no specific answer that I need to give.

माननीय अध्यक्ष **:** मंत्री जी, आप इन बातों का खंडन कीजिए, आपको लगता है कि गलत है तो खंडन करो। ये सब ऑन रिकार्ड जाना चाहिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मंत्री जी, आपकी बात का जवाब दे रही हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** केवल माननीय मंत्री जी का ही भाषण रिकार्ड में जाएगा।

? (*Interruptions*) *?*

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL : Please tell me if I am wrong. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आपकी बात का जवाब मंत्री जी दे रही हैं।

? (व्यवधान)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL: What is the policy regarding China and East Asia? ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I would like to inform the hon. Member that there is no restriction on the Member from talking on any issue. But this debate, this particular discussion is on the Supplementary Demands for Grants. You have asked me a question on what is the amount? You are taking money for Defence, now, what is our policy on China? I will say, why have I taken the money for Defence? And as Finance Minister, I am expected to explain and answer questions related to the Supplementary Demands for Grants, and that is exactly what I am doing. But this discussion today on the Supplementary Demands for Grants focusses on the Demands for Grants and not on the policy. You may ask that question when relevant, where relevant, and at the time when the discussion happens on this subject. ? (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, point of order ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Point of order! प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, Rajmohan Unnithan ji, I do not know if he is here, since he is not here, I would not raise it.

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** जिन माननीय सदस्यों ने सदन में बोला है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आप एक बात बताइए। क्या यह कोई अच्छा तरीका है कि माननीय सदस्य बोलकर चले जाएं? मैंने व्यवस्था दी है कि जो माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के जवाब के समय सदन में हैं, उनका ही जवाब दें।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** मैंने व्यवस्था दे दी है। अध्यक्ष की व्यवस्था ही व्यवस्था है। आप नेता हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** उनको सदन में रहना चाहिए।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **(**कलियाबोर**):** यह बात रिकॉर्ड में जाएगी कि यह माननीय सदस्य सदन में नहीं था। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** जनता ने उनको चुनकर सदन में बैठने के लिए भेजा है। जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो सदन में जवाब सुनने के लिए भी बैठना चाहिए।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** ये भी सदन में नहीं थे। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** राज्य मंत्री थे।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** यह क्या प्रक्रिया है? ? (व्यवधान) जनता रिकॉर्ड में सुन रही है। ? (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण**:** इधर जो हो रहा है**,** मैं भी सुन रही हूं। ? (व्यवधान) एमओएस भी इधर हैं और मेरा रिप्लाई राज्य सभा में था। **I** could not have been here. But I was listening, and that is why, I am answering specifically. And if hon. Member finds anything which is not pertinent, I am glad to receive that kind of a chiding from the hon. Member saying, ?you are not talking about what I spoke or you are talking something

different.? If I am not speaking pertinent, you are welcome to raise that issue. But again, hon. Member Gogoi tells you? ? (व्यवधान) आप स्पीकर साहब से कह दीजिए। ? (व्यवधान)

माननीय सदस्य गोगोई कह रहे हैं कि यह क्या प्रक्रिया है? मैं आपके आदेश के अनुसार जो मैम्बर प्रेजेंट है, उनके लिए जवाब दे रही हूं। यह मेरा निर्णय नहीं है, लिखित में रूल नहीं है, यह स्पीकर साहब की डायरेक्शन है। इससे आपको आपत्ति है तो स्पीकर साहब से बात करिए। मैं इधर कोई प्रक्रिया तय नहीं कर रही हूं। ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** माननीय अध्यक्ष जी, हम आपको ही दरख्वास्त कर रहे हैं।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आपने दरख्वास्त कर ली, अच्छी बात है। मेरा और कोई मकसद नहीं था, एक ही मकसद था कि जब मैम्बर्स बोलते हैं तो जवाब के समय सदन में रहें। मेरा यही विषय है।? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** क्या टाइम दिया गया था?? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** टाइम पता था कि आज जवाब देंगे।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** ढाई बजे जवाब देंगे या तीन बजे देंगे? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** यह भी बता देंगे ताकि मैम्बर्स उपस्थित रहें। गोगोई जी, अगर मैम्बर्स उपस्थित रहेंगे तो ठीक रहेगा।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** पहले ऐसा नहीं होता था।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** पहले ऐसा नहीं होता था। आप एक बात बताइए कि क्या आप इस मत से सहमत हैं या नहीं? समय तय कर देंगे, आपकी यह बात मान ली। लेकिन जो मैम्बर विषय को उठाते हैं, जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तब उपस्थित रहना चाहिए या नहीं?

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** आप टाइम बता दें। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** टाइम बता देंगे लेकिन उपस्थित तो रहना चाहिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** गोगोई जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या उपस्थित रहना चाहिए या नहीं?

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई **:** टाइम भी तो पता होना चाहिए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, Member Kathir Anand had spoken about how unfair treatment is being offered to the States on account of perceived inequity in taxes collected *vis-à-vis* quantum actually devolved to the States. Therefore, the allegation is the Centre is not giving as much as what is being collected from the States. Broadly, all hon. Members do appreciate and understand that this is not something which the Central Government decides. It is a formulation which is given by the Finance Commission. Based on the Finance Commission?s recommendation, timely, appropriate amounts are sent to the States directly. इसीलिए हमें केंद्र सरकार की ओर से कुछ करेक्शन कम ज्यादा करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अभी कॉंटेक्स्ट यह है कि अगले फाइनेंस कमीशन का अनाउंसमेंट, यानी कैबिनेट डिसीजन हो गया है। जिनको नियमित रूप से चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, उसके साथ नोटिफिकेशन आएगा। फाइनेंस कमीशन देश के हर राज्यों से मिलकर उनके ओपीनियन लेगा। उसमें जो भी स्टेट्स कहना चाहती हैं, उसे उन्हें फाइनेंस कमीशन से कहना चाहिए। Since this announcement or this question came from the Member, I want to, through you, submit that Tamil Nadu received about Rs. 1.29 lakh crore as devolution under the share of Central taxes. This is the 14th Finance Commission award. And the 14th Finance Commission is the one which raised the State?s share to 42 per cent. Earlier, it was 32 per cent. Now, during the 15th Finance Commission period, the 42 per cent became 41 per cent because of Jammu and Kashmir becoming a Union Territory. For the 15th Finance Commission period, as opposed to what they received during the 14th Finance Commission Rs.1.29 lakh crore, they will be receiving Rs.2.36 lakh crore in addition to the revenue deficit grant of Rs.6229 crore. Since the Member Kathir Anand ji is here, the answer is before him. ? (*Interruptions*)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): What is the collection from Tamil Nadu? That was my question. ? (*Interruptions*) You took a lot of money from the State as taxes. ? (*Interruptions*) What you gave back to the State, it was not proportionate. That was my question.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It cannot be proportionate. It will be under the formula given by the Finance Commission. Proportionality is decided by the Finance Commission and not by me. ? (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there is no argument on this. ? (*Interruptions*) I obey the Finance Commission just as I obey you here. So, the particular question asked by the Member is about the cesses and surcharges. I will give the details.

मैं हर सांसद को यह कहना चाहती हूं कि टैक्स कलेक्शन के बाद जो फाइनेंस कमीशन तय करता है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को जितना पैसा जाना है, उतना भेज देती है। आरोप यह है कि सेस और सरचार्ज कलेक्शन आज-कल ज्यादा हो रहा है, जिसका डीवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा नहीं होता और चूंकि अब राज्यों से सेस और सरचार्ज ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है, यह आरोप लगाने वाले तमिलनाडु से हैं, जिनका यह कहना है कि तमिलनाडु को सेस और सरचार्ज से डीवोल्यूशन नहीं मिलने के कारण उनको जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

मगर, सेस और सरचार्ज का विषय भी, जो हम कलेक्शन कर रहे हैं, वह मैं डाटा के साथ प्रूव करना चाह रही हूं कि कितना डीवोल्यूशन, not by Finance Commission, पर राज्यों को कितना गया। मैं बोल रही हूं, जो टोटल सेस कलेक्शन है, उसमें छ: कैटेगरीज हैं, प्रारंभिक शिक्षा कोष, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष, जीएसटी कंपेनसेशन फंड, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल डिजास्टर रेस्पांड्स फंड तथा नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड, ये दोनों मिलकर पाँचवे नम्बर पर हैं और छठा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है। इन सबको इकट्ठा करके वर्ष 2018-19 में, 14 लाख 4 हजार 882.50 करोड कलेक्शन हुआ है। वह ग्रैंड टोटल है।

The total cess collection including GST compensation cess is Rs. 26,08,980 crore. Of this, in 2018-2019, 53.86 per cent collection was allocated to the States. Now, progressively, this number has gone up, and I would like to say that in 2019-20, 102.99 per cent has been allocated to all the States. About 95.58 per cent has gone in the year 2020-2021, 97.70 per cent has gone in the year 2022, and 137.45 per cent has gone in 2022-23 which is a provisional number. And therefore, between 2018-19 and 2022-23, 99.32 per cent of all cesses collected have gone to the States.

Hon. Speaker, Sir, hon. Member Gaurav Gogoi has spoken about Disaster Relief Fund and special assistance to Andhra Pradesh and Tamil Nadu. ? (*Interruptions*) Yes, Sikkim. This is a particular and severe cyclonic storm. I am not sure if I can pronounce it right. I will spell it for you ? Michaung. I know it is a Burmese word. It has affected us. This cyclone has affected two States in varying degrees namely, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The glacial outflow affected Sikkim. With a view to help the State Governments to manage the relief necessitated by the cyclonic storm, the Ministry of Home Affairs has released, in advance, the Central share of second installment of the State Disaster Relief Fund of Rs. 493.60 crore to Andhra Pradesh, and Rs. 450 crore to Tamil Nadu. The Central Government has already released the first installment of the same amount to both the States. In addition, the State Government of Andhra Pradesh has an opening balance, in their SDRF

account, of Rs. 2,569.85 crore, and Tamil Nadu has an opening balance of Rs. 813.15 crore.

So, further, without waiting for the Memorandum from the State Governments, the Central Government has constituted the Inter-Ministerial Central Teams for both the States. I understand the Teams have gone to the States and have done their assessment of damages which have been caused by the cyclone. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Madam please check. With respect to Sikkim, the amount is very miniscule. It is less than ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No. Right. I will ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Are you aware of the damages?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes. Even I have gone to the border villages of Sikkim. I am quite conscious of what it means to them. ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, unfortunately, the details are not with you. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, I will give you the details. Do not worry. ? (*Interruptions*) I will give you the details. But even after that ? (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI: I am asking you to increase it because as compared to the States of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, the State of Sikkim has got only Rs. 44 crore. You can understand the difficulties faced by them. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, even for Tamil Nadu and Andhra Pradesh, these are advance payments. Sikkim will also get what is due to them and what the teams will assess and come back to us. I will give you the Sikkim figures as well.

Sir, further the Chennai basin project under the National Disaster Mitigation Fund includes Central Assistance of Rs. 500 crore. The Central Government is taking a proactive approach so that the urban flood mitigation project of Rs. 561.29 crore for integrated urban flood management activities can be taken up.

Sir, further, Members Gaurav Gogoi, Kathir Anand, Krishna Devarayulu and Mohd. Jawed of INC have questioned about inadequate allocation for MNREGA despite higher demand.

I have already explained this when I was responding to Shri Adhir Ranjan Chowdhury. It is a need-based allocation. As against the BE of 2023-24 Rs. 60,000 crore, we have now given another Rs. 20,000 crore. This will be to meet all those demands which many of the States have raised. This question was also raised by Members Jayadev Galla and K. Subbarayan.

I cannot see Shri Jayadev Galla. You are here, Sir. You have also raised a question of nutrient based fertilizer subsidy that it is not aligning. I want to highlight it because that is a specific mention which hon. Member picked up and I need to answer that. Total requirement under this head is Rs. 16,300 crore. Out of this, Rs. 13,351 crore is additional cash requirement and the balance amount, which is about Rs. 3,000 odd crore, is being met from internal savings and is within the demand. Therefore, there is no misalignment, although it does not appear so clearly as you would add it up.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: MNREGA says that we have to give job for 100 days.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, you will pick up every feature of the law which has been passed under you.

Sir, finally, there has been some kind of an aspect.

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** महोदय, वह जवाब नहीं देती हैं।

माननीय अध्यक्ष **:** उन्होंने जवाब तो दिया है कि आपने जो कानून पास किया है**,** सरकार उस पर चल रही है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण **:** महोदय, उसके हर एक पहलू पर बोलेंगे। जब उनके शासन के समय मनरेगा का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, कितने लोगों को मिला, नहीं मिला, सीएंडएजी की रिपोर्ट बोलती है कि जिन लोगों ने जन्म तक नहीं लिया था, मनरेगा के तहत उनको पैसा दिया गया है। उनकी पर्फार्मेंस यह है।?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** मैडम, मेरी बात सुनिए।?(व्यवधान) 2,92,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।?(व्यवधान) मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। कोई झगड़े की बात नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण **:** महोदय, ईश्वर प्रसाद जी का एफटी आर्टिकल पर कुछ ऑब्जर्वेशन आया है। कहा कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये लिखा, वो लिखा, वगैरह। Of course, it is again Prof. Saugata Ray. So, I need not refer to it. But that article refers to very many good points of achievement.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: This is House property.

माननीय अध्यक्ष **:** हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या पार्लियामेंट में किसी आर्टिकल पर बहस होगी? नहीं।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, I follow the Speaker?s order.

माननीय अध्यक्ष **:** अगर कभी कोई व्यक्ति कोई आर्टिकल लिख दें**,** तो क्या उस पर पार्लियामेंट में डिबेट होगी? नहीं।

? (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी **:** महोदय**,** मान लीजिए कि काम में फंसे हुए हैं।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप एक सीनियर नेता हैं।

? (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण **:** महोदय**,** इसीलिए मैं इसको हाइलाइट करना चाहती हूं।?(व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी **(**अनन्तनाग**) :** मैडम, मैंने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया था।

श्रीमती निर्मला सीतारमण **:** महोदय**,** जम्मू-कश्मीर की मांग कितनी थी और हमने कितना पे कर दिया है**,** यह भी बता दिया है। मैंने जेएंडके विषय पर बोला है।?(व्यवधान)

Macroeconomic fundamentals are fine. The Government has been, in a way, noticed for the fiscal discipline and reining in of high level of public debt. We are also being warned by certain observers that India must avoid squandering its economic potential. Therefore, the economic success of this Government, particularly of post-COVID period, is the contribution that the people of India are making.

हमारे भारत के भाई-बहन इस देश की तरक्की के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इस समय इसको नोटिस करके उसके लिए हम सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए। कठिन मेहनत के साथ किसान, वंचित लोग, पीड़ित, दलित, गांव में रहने वाले सब लोगों ने इस देश की भलाई के लिए मेहनत करके इस देश को इस कगार पर पहुंचाया है। इसको रिकग्नाइज न करके बार-बार कुछ न कुछ नेगेटिव बात करने वालों से आज हमारे अमृत काल के लिए आगे बढ़ने का संदेश नहीं मिलता है। वर्ष 2047 का हमारा संकल्प विकसित भारत है। हम सब उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस माननीय हाउस के सामने मांग रखती हूं कि इस सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स को पारित करें।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रेमचन्द्रन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Thank you very much, Sir. I did not get an opportunity to speak in the debate. I have a point regarding the economic situation of the State of Kerala. I am not subscribing to the allegations or the reasons stated by the Government of Kerala.

The Government of Kerala is alleging that a strong discrimination against the State is there. Its borrowing power is being reduced; the Revenue Deficit Grant is being reduced and also the divisible pool of taxes is not being paid. So many dues are also there. These points have been raised by the State Government.

It is a fact that Kerala State is under severe financial stress and burden. The State Government is not able to pay even for the Mid Day Meal Scheme. They do not have sufficient money for this. So, I want to ask a humble question to the hon. Finance Minister. Will the Government consider for some packages to be provided to those States which are under financial burden to enhance the ceiling limit of the borrowing power? Will the other demands of the State of Kerala be considered by the hon. Finance Minister?

माननीय अध्यक्ष **:** नहीं, ऐसे थोड़े ही होगा। कोई राज्य खराब वित्तीय हालत में है, तो केन्द्र उसको सहयोग करेगा, ऐसा थोड़े ही होगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** इस विषय पर जितने घण्टे आवंटित थे, उससे डबल चर्चा हुई है। इस पर आवंटित समय से डबल चर्चा हुई है। अब कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जाएगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयः अब मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

?कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10, 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 33, 35 से 38, 43 से 56, 58 से 66, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 85 से 98 और 100 से 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>15.42 hrs</u>

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS ?

FIRST BATCH, 2023-2024

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021?Contd.

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

?कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 15 और 18 के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<image: image003.jpg>

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

_____

15.42 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS ?

FIRST BATCH, 2023-2024

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021?Contd.

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

?कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 15 और 18 के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<image: image003.jpg>

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

_____

15.42 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS ?

FIRST BATCH, 2023-2024

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021?Contd.

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

?कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 15 और 18 के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<image: image003.jpg>

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

_____

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नंबर 20।